विकसित भारत में मध्यप्रदेश 2 ट्रिलियन डॉलर का देगा योगदान : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत ञ्च2047 के संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि देश की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में आयोजित 'विकसित मध्यप्रदेश' विषयक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी तथा उद्योग मित्र नीतियां लागू की गई हैं। राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल

वातावरण उपलब्ध करा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से प्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की विशेषता है कि जो एक बार यहां आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है और राज्य का भौगोलिक स्थान निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करता है। अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है।

डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इससे प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य ही नहीं, बल्कि उद्योग और निवेश के लिए भी पसंदीदा गंतव्य बन रहा है।

डायल-112 सेवा में बड़ा बदलाव

दो मिनट से ज्यादा की देरी पर सीधे अफसरों को मिलेगा अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में आपातकालीन पुलिस सेवा डायल-112 को अधिक तेज और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ी तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है। नई प्रणाली के तहत यदि किसी घटना की सूचना मिलने के बाद फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) 2 मिनट के भीतर घटनास्थल के लिए रवाना नहीं होता है, तो सिस्टम सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलर्ट भेज देगा। इस अलर्ट व्यवस्था में अब जिले के एडिशनल एसपी को शामिल किया गया है। अलर्ट में वाहन नंबर, थाना क्षेत्र और घटना की पूरी जानकारी स्वतः पहुंच जाएगी। पहले यह मॉनिटरिंग एसपी स्तर पर होती थी, लेकिन अब इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए एडिशनल एसपी स्तर पर शिफ्ट किया गया है।

पुलिस रेडियो मुख्यालय के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया

गया है क्योंकि कई जिलों में रिस्पांस टाइम बढ़ने और देरी की शिकायतें सामने आ रही थीं। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में वाहन समय पर रवाना नहीं होते थे, जिससे मदद पहुंचने में देरी होती थी। डायल-112 के ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 से 26 मई 2026 के बीच लगभग 9 महीनों में करीब 78 लाख लोगों ने आपातकालीन सहायता के लिए कॉल किया। इनमें से 21 लाख से अधिक मामलों में फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल मौके पर भेजे गए, जिनमें महिला अपराध और साइबर क्राइम से जुड़े मामले प्रमुख रहे।

नई व्यवस्था में यह भी तय किया गया है कि जैसे ही कोई कॉल प्राप्त होती है, उसे पहले 'एक्नॉलेज' और फिर 'एनरूट' अपडेट करना अनिवार्य होगा। यदि यह प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी नहीं होती, तो सिस्टम स्वतः उच्च अधिकारियों को अलर्ट जारी कर देगा।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए तय हों मानक : पटेल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।

केवल हितग्राहियों की प्रतिक्रिया के आधार पर गुणवत्ता का आकलन पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी मानकों के अनुरूप नियमित परीक्षण आवश्यक है। लोक भवन में आयोजित जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा की प्रतीक्षा करने के बजाय लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की रणनीति बनाई जाए।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश' समिट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 27 जून को रविन्द्र भवन में 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट' का आयोजन किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि समिट में मुख्यमंत्री भूमि आवंटन, भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यों के साथ एमएसएमई, स्टार्टअप तथा स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में एमएसएमई प्रदर्शनी और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' क्लिनिक का भी शुभारंभ किया जाएगा।

समिट की प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें एमएसएमई इकाइयों, स्टार्टअप्स, महिला स्व-सहायता समूहों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकों और विभिन्न संस्थानों की भागीदारी रहेगी। प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और बाजार विस्तार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम में राज्य के 2000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप प्रतिनिधि, निवेशक, वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग लेंगे।

लोक सेवा गारंटी के मामलों का समयबद्ध निराकरण करें : सीएस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी योजना के प्रकरणों का समय-सीमा में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विभागाध्यक्ष साप्ताहिक स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें तथा निचले स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण समय पर हो, जिससे प्रकरण उच्च स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता न पड़े।

बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने समय-सीमा में जवाब और दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट से स्वीकृत सभी प्रकरणों में आवश्यक आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

श्री जैन ने वर्ष 1947 से पूर्व के अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा कर उनके संशोधन अथवा निरसन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए नए विधेयकों और अधिनियमों को शीघ्र तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में शासकीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की प्रगति, साइबर अपराध, पॉक्सो एक्ट, मादक पदार्थों की रोकथाम तथा नवीन न्याय संहिता से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर भी चर्चा हुई।

राज्यपाल ने कहा- अति-गरीबों को प्राथमिकता से मिलें दुधारू पशु

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत दुधारू पशुओं के वितरण में अति-गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बैगा, भारिया और सहरिया जैसी अति-पिछड़ी जनजातियों के जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित करने पर जोर दिया।

लोक भवन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल पशु वितरण नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के पोषण और सतत आजीविका को मजबूत करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थियों को उत्पादित दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए दुग्ध संग्रहण, परिवहन और विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए। इसके लिए विभागीय अथवा थर्ड पार्टी सहयोग से आवश्यक वाहनों की उपलब्धता पर भी विचार करने को कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव ने बताया कि पशुपालकों को मोबाइल के माध्यम से पशु पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरल हिंदी में विकसित 'गोरस' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जो बिना इंटरनेट के भी कार्य करता है।

हफ्ते भर में घोषित होंगे शेष एल्डरमैन

नगरीय निकायों में पार्षदों के मनोनयन की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में शेष एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति अगले एक सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच इसको लेकर विचार-विमर्श पूरा हो चुका है। अब जिला स्तर से प्राप्त नामों की सूची पर अंतिम मुहर लगने का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के लगभग 244 नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया बाकी है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रमुख नगर निगम शामिल हैं।

एल्डरमैन की नियुक्ति

प्रदेश के 16 नगर निगमों में प्रत्येक में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, मुरैना, छिंदवाड़ा, देवास, कटनी, रतलाम, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। कई बड़े शहरों में नामों को लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है।

पहले भी हो चुकी है बड़ी नियुक्तियां

मार्च में राज्य सरकार ने 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की थी। उस समय नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कुल 768 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि कुछ क्षेत्रों, विशेषकर बुंदेलखंड और चंबल संभाग के कुछ निकायों की सूची सहमति न बनने के कारण होल्ड पर रख दी गई थी।अब शेष निकायों में नियुक्तियों के साथ पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी है।

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में बैठक 29 को

भोपाल : सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दिनेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2026 की समीक्षा बैठक 29 जून को 4:30 बजे आयोजित की गई है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रजिस्ट्रीकरण/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन) शामिल होंगे। बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बैठक में अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत एवं रिपीट मतदाओं की जॉच सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति गिरि को अर्पित की श्रद्धांजलि

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित स्व. वी.वी. गिरि की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और राष्ट्र के नव निर्माण में गिरि का योगदान अविस्मरणीय रहेगा।

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

लोकतंत्र अमर रहे!

संवैधानिक लोकतंत्र को बनाये रखने हेतु समर्पित एक कार्यक्रम

आपातकाल लागू होने के 50 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का समापन

संविधान हत्या दिवस 2026

भारतीय इतिहास के काले युग पर एक दृष्टि

"आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं; देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या के इस पाप को कभी नहीं भूलना चाहिए"
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

तिथि: 25 जून 2026 | समय: शाम 4:00 बजे
स्थान: सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग (CCRT), 15 - A, ब्लॉक डी, सेक्टर 7, द्वारका, दिल्ली

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण

विशेष प्रदर्शनी: संविधान हत्या दिवस एवं Long Live Democracy

लघु फिल्म की स्क्रीनिंग: 'संविधान हत्या दिवस'

स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल समय में जिन्होंने अत्याचार सहे और हिम्मत बनाये रखी, उन सभी को संगीतमय श्रद्धांजलि।

मुख्य अतिथि
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, भारत सरकार

विशेष उद्बोधन
श्री राम बहादुर राय
(आपातकाल में गिरफ्तार)
अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

CBC 09101/13/0014/2627